

‘तो छात्रवृत्ति क्या हुआ?’ हटी-पेपर लीक बिल पर प्रियंका गांधी ने किया तीख़ा हमला

नेशनल डेस्क । कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी काड़ा ने सोमवार को सवाल उठाया कि अगर छात्रों को अभी भी JAR के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, तो नए एंटी-पेपर लीक बिल का क्या मकसद है। संसद के बाहर प्रकाश में आते ही, कांग्रेस महासचिव ने बताया कि उन्हें NEET और CBSE परीक्षा के विरोध-प्रदर्शनों के बाद बिहार और पश्चिम बंगाल में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की अपर खबरें मिली हैं। गांधी ने कहा, ‘मैंने सुना है कि बिहार और बंगाल में छात्रों के खिलाफ अभी भी JAR दर्ज की जा रही है। मैंने यह सुना है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो, मेरा मतलब है... फिर इसका क्या मतलब है?’ उन्होंने यह टिप्पणी मौनसुन सत्र से ठीक पहले आई है, जिसमें केंद्र सरकार लोकसभा में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश करने वाली है।

बहुजन हिताय!



बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 254 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 28 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन

के सदस्य बनें

E-mail :

rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती ग्रवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

राहुल को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की तैयारी?: निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, विदेश यात्राओं की हो एसआईटी जांच



नई दिल्ली। लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठाया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा जल्द उन्हें विपक्ष के नेता के पद से हटाने का प्रस्ताव पेश करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। 2004 से 2026 तक, उनकी किसी भी विदेश यात्रा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। राहुल गांधी ने अब

तक जितनी भी यात्राएं की हैं। उनमें उन्होंने सरकार और संविधान के खिलाफ बात की है। हम उन्हें विपक्ष के नेता के पद से हटाने का प्रस्ताव पेश करने की कोशिश करेंगे।' ये टिप्पणियाँ तब आई जब विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग की। विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए दुबे ने कहा कि सवालियों के जवाब सरकार के बजाय राहुल गांधी

को देने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता की पिछले कई वर्षों की विदेश यात्राओं को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है। भाजपा सांसद ने आगे तर्क दिया कि विदेश यात्रा के दौरान विपक्ष के नेता की जिम्मेदारियाँ राष्ट्रीय प्रतिनिधि के समान होती हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारत की नीतियों को प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, 'वह विपक्ष के नेता हैं, और जब विपक्ष के नेता विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो उन्हें एक तरह से प्रधानमंत्री की भूमिका निभानी पड़ती है। उन्हें लोगों को भारत की नीतियों के बारे में बताना होता है। हालाँकि, राहुल गांधी ने जब भी विदेश यात्रा की है, उन्होंने हमेशा भारत, सरकार और संविधान के खिलाफ ही बात की है।' दुबे ने यह भी कहा कि वह राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के पद से हटाने की मांग करेंगे और सरकार से कांग्रेस नेता की विदेश यात्राओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आग्रह किया।

पेपर लीक के बाद अब ई20 की बारी!: केजरीवाल बोले- एक होकर आवाज उठानी होगी; कॉस्टीट्यूशन क्लब में जुटने को कहा



नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक के बाद एक बार फिर से ई20 मुद्दे को उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि शनिवार को दिल्ली में टाउनहॉल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा है। केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे को देश के युवाओं और लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'देश के युवाओं ने एक होकर आवाज उठाई तो धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ई20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी। इस शनिवार हम

'नेशनल टाउनहॉल ऑगस्ट ई20' आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शामिल होकर आप ई20 पर अपनी बात रख सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं।' अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ई20 का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री से अपील की कि लगे हाथ इसका भी समाधान कर दी जाए। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनकी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। केजरीवाल ने ई20 के खिलाफ दिल्ली में एक टाउनहॉल आयोजित करने की बात कही। इस दिशा में सभी लोगों को साथ लाने के लिए इस शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित

कर रहे हैं, 'नेशनल टाउनहॉल ऑगस्ट ई20'। इसमें हमें उम्मीद है कि हजारों लोग शामिल होंगे। 12 बजे दिन में शुरू होगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, 'जो लोग दिल्ली और आसपास के शहरों से हैं वो कॉस्टीट्यूशन क्लब में सुबह साढ़े 11 बजे तक पहुंच जाएं। जो लोग दिल्ली से बाहर हैं और नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन जुड़ें। हमें उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे, जो लोग नहीं आ सकते वो 8588833212 पर वॉट्सएप कर देंगे। हम शुक्रवार शाम तक एक लिंक भेज देंगे। आप इस पर क्लिक करके हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं।' केजरीवाल ने कहा, 'इस टाउनहॉल में हम इस मुद्दे में दिलचस्पी रखने वाले सभी ऐक्सपर्ट को और सभी पीड़ितों को, जो भी टुट्टी है इस मुद्दे हैं, जिनकी गाड़ियाँ खराब हो गई हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और बोलने का मौका देंगे और सरकार को ई20 पॉलिसी वापस लेने के लिए मजबूर करने की भविष्य की रणनीति तय करेंगे।'

अस्पताल से राजघाट पहुंचे वांगचुक, बोले- बापू का रास्ता आज भी प्रासंगिक, शांति से रखें अपनी बात

दिल्ली/गुरुग्राम ।

कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी पत्नी गीतांजलि आंग्मो के साथ सोमवार को राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद यहां पहुंचे थे। वांगचुक ने 26 दिन के उपवास और आंदोलन के समापन के बाद यह श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने अपने विचार साझा किए। वांगचुक ने कहा कि वह सबसे पहले महात्मा गांधी को याद करना चाहते थे। उन्होंने गांधीजी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने देश को यह बताया कि गांधीजी का दिखाया रास्ता आज भी उतना ही सही और प्रासंगिक है जितना सौ साल पहले था। पिछले पांच-छह साल से वे लद्दाख में गांधीजी के इस तरीके को अपना रहे हैं। उन्होंने पाया कि यह तरीका बहुत सही और प्रासंगिक है। उन्हें बहुत यकीन नहीं था कि यह राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा या नहीं। मैं देश के लोगों को बधाई देता हूँ: सोनम वांगचुक



एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने राजघाट पर कहा कि मैं देश के युवाओं, आम लोगों और सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं बुजुर्गों, हर उम्र के लोगों और उन युवा आयोजकों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस आंदोलन को इतनी शांति से आगे बढ़ाया। हमें यह समझना होगा कि अगर कोई समाधान या कामयाबी मिली है, तो वह हमारी ताकत या लाठी-पथर के इस्तेमाल से नहीं मिली है। बल्कि, यह शांति की अपील और हमारी अपनी तकलीफों से मिली है। इस्तीफा तो बस शुरुआत: सोनम वांगचुक

धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि इस्तीफा तो बस शुरुआत है। अगर अब से इस मुद्दे को माना जाए और उस पर काम किया जाए, तो हमारा देश बेहतर बनेगा। मेरी नजर में यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। अभी बातचीत चल रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सकारात्मक बातचीत के जरिए देश के लिए सबसे सही रास्ता अपनाया जाएगा, जिससे हम आपसी सद्भाव से एक बेहतरीन सिस्टम लागू कर सकेंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल

वांगचुक ने विश्वास दिलाया कि समाधान जरूर निकलेगा। उन्होंने माना कि इसमें समय लग सकता है, लेकिन इसका अंत अंधेरे में नहीं होता। उन्होंने खुद यह देखा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पहली बार में सफलता न मिले, लेकिन आमतौर पर सफलता मिल ही जाती है। अस्पताल से वीडियो बनाते हुए सोनम वांगचुक ने कहा था कि लोगों ने अपनी आवाज उठाई और इस महत्वपूर्ण आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'हम सफल हुए' और यह सभी के प्रयासों का परिणाम है। सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो संदेश में स्वास्थ्य में हो रहे सुधार पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। अब उनकी स्थिति पहले से काफी बेहतर है। शरीर में धीरे-धीरे ऊर्जा वापस आ रही है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को भी धन्यवाद दिया। वांगचुक ने लद्दाख के आंदोलन को मिले व्यापक समर्थन के लिए जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने लोगों की एकजुटता और अपनी आवाज उठाने की सराहना की। वांगचुक ने अपने संदेश में आंदोलन की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह जीत उन सभी की है जिन्होंने इस मुहिम में साथ दिया।

कब होंगे केस वापस, अब तक नहीं आया सरकारी आदेश



नई दिल्ली । दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन और हिंसा से जुड़े मुकदमों को वापस लेने की अटकलों के बीच, यह स्पष्ट हुआ है कि फिलहाल सरकार की तरफ से केस वापसी को लेकर कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। आदेश जारी होने के बाद ही कानूनी प्रक्रिया के तहत मामलों को वापस लेने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन, हिंसा और इससे जुड़ी अन्य घटनाओं में कुल 20 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों का विवरण इस प्रकार है- 14 केस: सीधे तौर पर प्रदर्शन और हिंसा से जुड़े हुए हैं। एक केस: क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने को लेकर दर्ज है। अन्य केस: पत्रकारों द्वारा कवरेज के दौरान खुद के साथ हुई मारपीट और हमलों को लेकर दर्ज कराए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद केस वापसी की एक तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सरकारी आदेश प्राप्त होने के बाद, अभियोजन पक्ष (यानी दिल्ली पुलिस) की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को एक आधिकारिक पत्र लिखा जाएगा। इस पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा जाएगा कि पुलिस/अभियोजन इन मामलों में आगे कोई कार्रवाई (प्रोसिक्यूशन) नहीं करना चाहती है। पत्र भेजने के बाद उपराज्यपाल की मंजूरी (अप्रुवल) का इंतजार किया जाएगा। एलजी की मंजूरी मिलने के बाद, दिल्ली पुलिस संबंधित अदालत (कोर्ट) को आधिकारिक तौर पर सूचित करेगी कि वह इन मुकदमों में आगे मुकदमा नहीं चलाना चाहती है। पुलिस के इस आवेदन के बाद, केस को पूरी तरह से रद्द या वापस करने का अंतिम निर्णय अदालत के आदेश पर ही निर्भर करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में एक अहम बात यह है कि जिन मामलों में पत्रकारों ने खुद पर हुए हमलों और मारपीट की शिकायतें दर्ज कराई हैं, उन पर केस वापसी का नियम लागू नहीं होगा। पत्रकारों द्वारा दर्ज कराए गए ये मामले वापस नहीं लिए जाएंगे और इन पर कानूनी प्रक्रिया अपने तय तरीके से आगे बढ़ेगी।

क्या बिहार में चली एके-47?: राहुल के दावों पर भाजपा का पलटवार, अराजकता फैलाने का लगाया आरोप, कहा- मांगें माफी

नई दिल्ली। भाजपा ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल, राहुल गांधी ने बिहार में आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ एके-47 राइफलों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। भाजपा ने राहुल गांधी पर विरोध प्रदर्शन भड़काने और अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस झूठे और मनगढ़ंत दावे को फैलाने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सत्ताधारी पार्टी ने गांधी के बयान को न केवल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बल्कि एक पाप करार दिया। यह प्रतिक्रिया तब आई जब राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि रिपोर्टरों से पता चलता है कि बिहार में

प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एके-47 राइफलों का इस्तेमाल किया गया था। सैकड़ों को गिरफ्तार कर एफआई दर्ज किया गया था। उन्होंने छात्रों पर हुए कथित हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के नेता की ओर से दिखाई गई अत्यंत गैरजिम्मेदारी बेहद शर्मनाक है। पात्रा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वाारा एके-47 के इस्तेमाल के बारे में बात की। यह बिल्कुल निंदनीय है कि इस तरह की झूठी बातें भारत में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन



व्यक्ति द्वारा फैलाई जा रही हैं। राहुल गांधी से क्या सवाल पूछा? राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की मांग करते हुए पात्रा ने कहा, 'वे अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एके-47 - मैं राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल

किए गए इस शब्द पर जोर दे रहा हूँ। क्या इस देश में पुलिस ने कभी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए एके-47 का इस्तेमाल किया है? क्या ऐसा कभी हुआ है?' 'राहुल गांधी यह कैसे कह सकते हैं

कि एके-47 का इस्तेमाल किया गया है? यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। राहुल गांधी को इस तरह की अफवाहें और झूठ फैलाने के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।' राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाया? केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत के बाद कॉन्ग्रेस जनता पार्टी द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करने का जिक्र करते हुए पात्रा ने कहा, 'इस तरह का दुष्प्रचार करके और इस तरह की गलत सूचना फैलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में दहशत, अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। यह बेहद आपत्तिजनक है।'

पात्रा ने आरोप लगाया, 'स्वाभाविक रूप से, (समस्याओं का) समाधान करना राहुल गांधी का उद्देश्य नहीं है। हंगामा खड़ा करना, कृत्रिम आक्रोश पैदा करना, विरोध प्रदर्शन करवाना और सबसे बढ़कर अराजकता फैलाना ही राहुल गांधी और विपक्ष का एकमात्र लक्ष्य है।' बता दें कि कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाड़ा सहित विपक्षी सांसदों ने सोमवार को संसद भवन परिसर में बहुध्वज परीक्षा के पेपर लीक मुद्दे पर हुए आंदोलन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस बर्बरता के विरोध में प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी मांगने की मांग की।

स्वरोजगार की पहल

प्रधान का नुकसान क्या राहुल का फायदा है?

संस्था को यात्रा प्रौद्योगिकीयक नहीं माना हो। यह
गोपनीय के उस करियर में यह फैसला ठीक जैसा है, जो
नहीं है अधिक परिणामों में पराजित हुआ है।
कठिन रणनीतिकारों के लिए सबक यह है कि
सिखावत को रणनीति, जब मध्यम वर्ग को
आकांक्षियों को सौंपे और प्र प्रभावित करने वाले
निसि मुद्दे, जैसे धरती की प्रेषण, छिन्न
भविष्य, के साथ जोड़ दी जाए, तो यह अन्यथा
प्रभावशाली भाषण के खिलाफ निर्णायक साबित
हो सकता है। क्या वह आगामी युवा जनता में
करार साबित होगी? अब अस्सी प्रेषण उस
प्रदेश में होगी, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव
होने हैं। अफेलिया यादव और ठाकुर पोलो
इच्छाफल फलें हैं इन विरोध प्रदर्शनों में खुल और
शिक्षा के माध्यम से चुनने हैं और उनमें पहले
के चुनाव प्रचारों के 'यू.पी. के लड़के, यू.पी. की
लड़कियाँ' नारे को फिर से जीवित कर दिशा है।
निसि चुनाव में निश्चिन्तजनक परिणाम मिले
यु.पी. के रणनीतिकार अब प्राप्ति के दृष्टिकोण को
एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश
करें-यह साबित करने कि सरकार को दूसरा शान
सकता है और उनमें छत्र और मध्यमवर्गीय
महजदतियों को एकजुट करना, जो नींद घोलते
खुद को ठाण महसूस कर रहे हैं। रणनीतिक मत
को धरण जब शुरू नहीं होता जब कोई नींद दृष्टिकोण
देता है, बल्कि जब शुरू होता है, जब जनता को
पता चलता है कि सभी शक्तिशाली सरकार थी
उन दायज के अर्थ चुकने को विवश हो सकती है।
खुल और ठाकुर स्थानों उस एक कठिन संघर्ष में
मिली जीत को स्थायी रणनीतिक पुंजी में बदल
फैला है या नहीं, सामाजिक उत्तर प्रदेश में, यह
करेगा कि 25 जुलाई, 2026 को विपक्ष के अंतर्गत
मजबूत होने के क्षण के रूप में यह किता जाएगा
या धनबाद के निरंतर वर्चस्व के दौर में एक दुर्लभ
अपवाद के रूप में।

सरकार की व्यवस्था कैसे सुधरे?

[illegible]

जोर-जोर के नारों या बड़ी भीड़ से नहीं बनेगा भारत का भविष्य

पर, हर कोई हार जाता है। मूल कारण अविश्वसनीयता खो देता है, संवाद की जगह डोलता है और एण्ट्रेंकडुट होने की बजाय विभाजित हो जाता है। लोग अंततः सार्वजनिक हित के नाम की रूढ़ तबदीली की नीमत चुकाते हैं। भारत सिर्फ और राष्ट्र नहीं है। भारत एक संघ्यता है, जिस हजारों वर्षों से दुनिया को शांति, सिग्नियता, कानून और आत्म-संयम के मूल्य सिखाए हैं। यह भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अनगिनत संतों की भूमि है, जिन्होंने माना कि सार्वजनिक सत्य, धर्म और संवाद से आता है, न कि या हिंसा से नहीं। 'यसुरैव कुरुद्वकम' का हार्दिक दर्शन हमें याद दिलाता है कि तुनिया एक परिवर्तन प्राप्त भावना को हमारे सार्वजनिक जीवन में मार्गदर्शन करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि पक्ष तर्क के साथ प्रतिष्ठित हों। गोपीर राष्ट्रीय भूमि पर राष्ट्रीय बातचीत के एकदूर हैं। उन पर सभ्यता में बहस होनी चाहिए, विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, जहाँ आवश्यक हो अदालतों द्वारा जांच जानी चाहिए और नागरिकों तथा सरकारों के संवाद के माध्यम से संबंधित किया जाना चाहिए। लोकतंत्र तब सबसे मजबूत होता है जब विचारों की टकराव है, कि एक जब गुस्से टकराते हैं। हर मनुष्य स्वयंका नही किन्ना जा सकता। सरकारों जिम्मेदारी है कि वे विचार करें कि क्या यह निर्यात वैध, आर्थिक रूप से संभव है और व्यापक जनता में है? समान रूप से, सरकारों को सार्वजनिक चिन्ताओं को ईमानदारी से सुनना चाहिए। लोगों को नजरअंदाज करना केवल निराशा को गहरा करता है। सम्मानजनक संवाद हमेशा चुपची से आर्थिक मजबूत होता है। राजनीतिक दलों को भी एक जिम्मेदारी है। हर सार्वजनिक मुद्दे राजनीतिक अंक बढ़ोने के अवसर नहीं बनना चाहिए। नागरिक ऐसे नेता

हृदयकार है जो भावनाओं को शांत करे, चर्चा को प्रोत्साहित करे और विभाजन को भंग करने की बजाय समाधान खोजे। मौडिबा को भी अपने प्रभाव को फहचानना चाहिए।

हालांकि लोकतंत्र में रिपोर्टर आवश्यक है लेकिन सनसनीखेज खबरें कभी-कभी तनाव को भड़का सकती हैं। सबसे ऊपर, हम में से प्रत्येक को नागरिकों के रूप में एक जिम्मेदारी है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारे कार्य किसी समस्या को हल करने में मदद करते हैं या केवल लाखों निर्दोष लोगों के लिए जीवन को कठिन बनाते हैं? लोकतंत्र हमें अधिकार देता है लेकिन यह जिम्मेदारी की भी अपेक्षा करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कभी भी धमकी, हिंसा या व्यवधान का बहाना नहीं बननी चाहिए। विरोध की ताकत सड़कों के जाम होने या इससे होने वाली व्यवधान की मात्रा से नहीं मापी जाती। यह इसके तर्कों को ताकत, इसके प्रतिभागियों के अनुशासन और इसके उद्देश्य की नैतिक शक्ति से मापी जाती है। आइए विरोध करने के पवित्र अधिकार की रक्षा करें लेकिन हम उन सभी निर्दोष नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करें, जो बस शांति से अपना दैनिक जीवन जीना चाहते हैं। आइए ठकुराव को बातचीत से, गुस्से को तर्क से और व्यवधान को संवाद से बदलें। भारत का भविष्य जोर-जोर के नारों या बड़ी भीड़ से नहीं बनेगा। यह विचारशील नागरिकों, जिम्मेदार नेताओं और उन संस्थानों द्वारा बनाया जाएगा, जो निष्पक्षता के साथ सुनते हैं। हमारा लोकतंत्र अवैध संघर्ष का थिएटर बनने के लिए बहुत कोमती है। हर विरोध उस गरिमा, शांति और बुद्धिमत्ता को प्रतिबिम्बित करे, जो हमेशा से भारत की सबसे बड़ी ताकत रही है। तभी हमारी आवाजें वास्तव में बदलाव को प्रेरित करेंगी, न कि डर को।

अस्तित्व की दिशा में उत्तर प्रदेश की अभिनव पहल

उत्तर प्रदेश में बड़ी राफा आबादी, वेनी से हो रहे नगरिकरण और प्राकृतिक अवसरो में निरंतर सुधारों के कारण बंदरों उत्पन्न स्थानों के बीच संबंधों को घटाना लगातार बढ़ रहा है। राहों और कस्बों में बंदरों को बड़ी संख्या से जहाँ आनन को जन-मल को हानि, दुर्घटनाओं और दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहीं अपने और बंदर भी अपने प्राकृतिक आवसरो और भोजन के अभाव में आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आने के लिए विवश हो जाते हैं। यह स्थिति केवल आने के नुकसान नहीं है, बल्कि पर्यावरण को नुकसान और वन्यजीवों संरक्षण के दृष्टिकोण से भी अक्षीर विषय है। इसी चुनौती का शायी और प्रकृति सांवाहित सामान्य कोनने के उद्देश्य से प्रदेश के प्राकृतिक स्थानों योगी आदिनाथ जैन ने 'एक पैड़ मू के नाम' वृक्षारोपण महारूप-2026 के अंतर्गत 'कपि वन' को अभिनव अवधारणा को साकार किया है। यह फल केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव और वन्यजीवों के बीच सामंजस्य स्थिति मानव, पर्यावरण संरक्षण को बांधा देने तथा बंदरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में भोजन और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मानव और बंदरों के बीच बढ़ता संघर्ष

अनेकों का निर्माण किया। इस योजना का उद्देश्य बंदों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध करना है, ताकि वे भोजन की उल्लास में रहें और जंगलों में प्रवेश न करें। कृषि वन ऐसे हरित क्षेत्र हैं, जहाँ बंदों के लिए पूरे वर्ष प्राकृतिक रूप से भोजन उपलब्ध रहे तथा उन्हें सुरक्षित आवास भी प्राप्त हो।

अवनत भूमि का उपयोग

प्रदेश में कृषि वन की स्थापना के लिए ऐसी भूमि का चयन किया गया, जो अवनत अथवा कम उष्णयों में आने वाली थी। इससे एक ओर अनुपयोगी भूमि का फलवरीणीय रूप में प्रत्युपयोग हुआ, वहीं दूसरी ओर नए हरित क्षेत्र विकसित करने का अवसर मिला। इस फल से बेहतर एवं अवनत भूमि को भी फलवरीण संरक्षण की मुख्यधारा में जोड़ दिया।

फलदार प्रजातियों का वैज्ञानिक चयन

कृषि वन की सभ्यता महत्वपूर्ण विरोधता यह है कि इसमें लगाए गए पौधों का चयन वैज्ञानिक आधार पर किया गया है। ऐसे फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं जिनमें अलग-अलग मौसम में फल आते हैं, ताकि बंदों की वर्षभर प्राकृतिक भोजन उपलब्ध हो सके। कृषि वन में मुख्य रूप से बड़हन, आम, जामुन, अमरवट, बेन, फुल, कटहल, जै, शहतूत,

पल्लट और अनौर जैसी प्रजातीयों का रोपण किया गया है। इन वृक्षों में न केवल बंदरों की भीजन मिलेगी, बल्कि अनेक फलियों, मिलाचटियों और अन्य फलफूलों के लिए भी प्राकृतिक आवास और खाद्य स्रोत विकसित होंगे। फलदार वृक्षों की यह श्रृंखला जैव विविधता को बढ़ाने, परागण करने वाले जीवों के संरक्षण तथा स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

प्रदेशव्यापी अभियान

प्रदेश में 21 जुलाई 2026 को यह अभियान का उद्घाटन प्रमुख के अगुआई में एक साथ आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष में एक साथ संचालित किया गया। प्रत्येक नगर निकाय के बाहरी क्षेत्र में न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि पर कृषि वन विकसित किया गया। इस अभियान के दौरान प्रदेशभर में 21,75,55 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2,43,049 फलदार पौधों का रोपण किया गया। प्रदेश द्वारा स्थापित किए जा रहे कृषि वन केवल एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर पर्यावरण को पर्यावरणीय एवं वन्यजीव संरक्षण को जोड़ता है।

नगर विकास एवं आवास विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका

कृषि वन की स्थापना में नगर विकास विभाग द्वारा

विकास विभाग विभाग ने व्यापक संशोधन एवं सहभाषिता किया। नगर निगमों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का जबरन, पौधोपयोग स्थलों का विकास, स्थानीय स्तर पर समन्वय तथा पौधों को सुरक्षा सुनिश्चित करने में इन विभागों को भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमि चिह्नित कर पौधोपयोग कराया। अक्सर विकास विभाग ने भी अपने निरीक्षणशील क्षेत्रों में पौधे वन विकासित करने में सक्षम संशोधन प्रदान किया। दोनों विभागों की सहभाषिता ने दूसरे विभागों को प्रेरणायुक्त नगरीयता के दायरे प्रदान किया।

कृषि वन केवल चरों के लिए भीशन उपलब्ध करने का सीमित नहीं है। इसी फलस्वरूप संशोधन को भी व्यापक लाभ प्राप्त होगा। बड़े संख्या में फलदार वृक्ष लगाए जाने से हरित क्षेत्र का विस्तार होगा, कृषक अश्वशोण बोहेगा, गुण गुणवत्ता में सुधार आरंभ तथा स्थानीय जलवायु संतुलित होगी। फलदार वृक्षों से पशुधर्म और अन्य जीव-जंतुओं को भी प्राकृतिक आवास मिलेगा, जिससे क्षेत्र-विकास का संरक्षण होगा। भविष्य में ये क्षेत्र जेट-विशेषता वाली वन के रूप में विकसित होकर फलदारवृक्ष प्रत्यक्ष को मानव को करिग

प्राप्ति वन को अत्यन्त प्राण-वर्धक वन्यजीवों के बीच सर्वप्रथम को कम करने का प्रकृति आधारित उद्देश्य सम्मान है। यदि बंदरों को उम्मेद प्रस्तुत करता है तो यह भी मान्यता प्राप्त है कि वे अपने वातावरण में पर्याप्त भोजन और सुरक्षित स्थान उपलब्ध होगा तो उन्हें अवश्य बने रहेंगे। वे अपने जीवन में सफलतापूर्वक काम करेंगे। इसमें दोष नहीं मूल्यों दोनों को सुरक्षा सुनिश्चित होने तथा संस्था की पटनाओं में मुक्ति आयेगी। यह फल वन्यजीवों संरक्षण और वनीकरण के बीच संतुलन स्थापित करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी मामला में वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों की भागीदारी जन्म लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'एक पेड़ का नाम' कार्यक्रम मार्च 2026 के अंतर्गत स्थापित किए गए वन पर्यटन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को दिशा में एक दूरदर्शी और ऑफिस पहल है। प्रस्ताव में 21,75,59 हेक्टेयर क्षेत्र में 2,43,04 फलदार पौधों का रोपण कर बंदरों के लिए प्राकृतिक भोजन और सुरक्षित आवास विकसित करने का प्रयास न केवल मानव-बंदर संबंध को कम करेगा, बल्कि उनके विविधता के संरक्षण, हमारे देश के विकास और पर्यटनपीठ संतुलन को भी महत्वपूर्ण प्रदान करेगा।

लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सरकार लाई सख्त एंटी पेपर लीक कानून इस बीच सरकार ने सोमवार को लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक के मामले में दोषियों को 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। साथ ही ऐसे मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक ऐसे समय लाया गया है जब नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में छत्रों के बड़े आंदोलन हुए और इसी विवाद के बीच धर्म प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष ने विधेयक पेश होने के दौरान भी संसद में हंगामा किया और छत्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा।

काफी कम होने जमीन के रिकॉर्ड हासिल करने में देरी कम होने और एंड-टू-एंड डिजिटल वर्कफ्लो के जरिए पारदर्शिता बढ़ने का उम्मीद है। यह ऑनलाइन सिस्टम हर एप्लीकेशन और मजबूती का पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखकर जवाबदेही भी मजबूत करेगा। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपलोड किए गए रिकॉर्ड्स के सही होने का जिम्मेदार संबंधित पटवारी या राजस्व अधिकारी की तय की गई है। अपलोड करने के बाद किसी भी सुधार की प्रक्रिया केवल तय आधिकारिक प्रक्रिया के जरिए ही की जाएगी। वित्त आयुक्त ने कहा कि यह पहल राज्य की राजस्व प्रशासन की आधुनिक बनाने और टेक्नोलॉजी-आधारित, नागरिक-अनुकूल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी सेवाएँ पहुँचाने की व्यापक कोशिशों का हिस्सा है, जिससे जमीन के रिकॉर्ड तक पहुँच तेज, ज़्यादा पारदर्शी और पेशानी-मुक्त हो सकेगी।

संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। उनकी दूरदृष्टि, उच्च जीवन-मूल्य और उत्कृष्टता के प्रति अटूट समर्पण ने देश के करोड़ों युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा दी। उनका जीवन और व्यक्तित्व आज भी युवाओं को कड़ी मेहनत, नवाचार और राष्ट्र-निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करता है।

सभी विद्यालयों में छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने, प्रीतियों का वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निष्करण कर, तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों में अभिभावक बैठक, जागरूकता कार्यक्रम एवं परामर्श सत्र आयोजित कर अधिक से अधिक पात्र बालिकाओं का समयबद्ध टीकाकरण सुनिश्चित करने पर बल दिया।

बैठक में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कार्ययोजना बनकर एहपवी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।

रिजिजू ने विपक्ष से कहा- देश आपको देख रहा, सदन चलने दें

नई दिल्ली। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को बार-बार बाधित होती रही। शाम 5 बजेकर 15 मिनट जब सदन की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई तो संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर कर चर्चा नहीं होने दे रहा है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा?
इसके जवाब में राज्यसभा में प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं और हम चर्चा में ठरने वाले नहीं हैं। दरअसल, विपक्ष का कहना है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस एक्शन के मामले में गृहमंत्री को बयान देना चाहिए। किरन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से अपील करते हुए कहा कि उसमें उम्मीद थी कि वह अपनी पार्टी के सांसदों को सदन चलाने के लिए समझाएंगे।

रिजिजू ने विपक्ष पर क्या आरोप लगाया?
रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को लेकर चर्चा की मांग करती रही है, लेकिन अब जब सरकार 'पब्लिक एम्प्लॉयमेंट (प्रिवेशन ऑफ़ अनफ़ेयर मींस) संशोधन विधेयक' जैसे महत्वपूर्ण



“**हम चर्चा को तैयार हैं**”
-मल्लिकार्जुन खरगे

आइए, चर्चा कीजिए!
- किरन रिजिजू



विधेयक पर चर्चा कराने को तैयार है, जब विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में चर्चा के लिए समय निर्धारित

कर दिया है। रिजिजू ने विपक्ष से क्या कहा? संसद की बिजनेस सलाहकार समिति को बैठक में विपक्ष को

सहमति से समय आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्री भी सदन में चर्चा सुनने के लिए मौजूद हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, 'बाहर कहा जाता है कि

संसद में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन सदन के भीतर हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आइए, चर्चा कीजिए। फिर भी आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं।' संसदीय

कार्यमंत्री ने खरगे से कहा कि वह विपक्ष नेता हैं और कांग्रेस सांसदों को इस तरह का व्यवहार न करने का सलाह दें। देश के युवा इस कार्यवाही को देख रहे हैं और वे

प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ विधेयक लोकसभा में पेश, 7 साल की कारावास और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। (वेबदार्ता) सरकार ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रवधान कानून विधेयक संसद के लोकसभा में पेश किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में विपक्षी सदस्यों के हाथों के बीच लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। विपक्षी सदस्य दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर जवाबदेही तय करने और

गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे। अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में संशोधित अपराधों के लिए कम से कम सात साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी

पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा सुनना चाहते हैं। रिजिजू ने यह भी कहा कि लोकसभा में सरकार ने वक्तव्यों को सूची तक जारी कर दी है, लेकिन वहां भी कांग्रेस के सदस्य हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से कहा कि इस तरह के रवैये से सबसे अधिक नुकसान उसी का होगा। अब संसद में चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री पहले ही इस मुद्दे पर आवश्यक कदम उठा चुके हैं और अब संसद

में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष उसे होने नहीं दे रहा। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसदीय कार्यमंत्री को इन बातों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि वे चर्चा को तैयार हैं, लेकिन वह छात्रों पर बल प्रयोग का मुद्दा उठाने रहे। खरगे जब अपनी बात रख रहे थे तो राज्यसभा में जबरदस्ती हंगामा शुरू हो गया और उपसभापति ने सदन को कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।

:- सीजेपी की सरकार को चेतावनी :- छात्रों पर पुलिस एक्शन रोकें, वरना फिर से धरने पर बैठ



नई दिल्ली। जंतर मंतर से घटना खत्म कर लौटो कार्यक्रम जनता पार्टी ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने एक ट्वीट किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को टैग करते हुए समझौते के अनुसार काम न होने की बात कही है। रंका ने

कहा कि समझौते में कहा गया था कि आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद भी बिहार और चंपारण में बड़े संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में रैकड़ों छात्रों को सख्तियां लगाई गई हैं। ऐसा कई राज्यों में हो रहा है। दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों में

प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आई है। हमारी रिपोर्ट है कि छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी केसों की तुरंत वापस लिया जाए, इसके अलावा भविष्य में भी इस आंदोलन से जुड़े मामलों में केस दर्ज न किए जाएं। हमारी रिपोर्ट है कि कल तक आप इस संबंध में हमें जानकारी दें

यह बताएं कि भारत सरकार क्या कर रही है या करेगी। खरों नहीं उन्होंने कहा कि यदि इन केसों को वापस नहीं लिया गया और पुलिस का एक्शन जारी रहे तो हम फिर से जंतर मंतर पर बैठने को मजबूर होंगे और आंदोलन करीबना अनंतकाल तक जारी रहेगा। पुलिस केस दर्ज हुआ है या फिर उन्हें अरेस्ट किया गया है। आशुतोष रंका ने भी किसी केस का उदाहरण अपनी बात में नहीं दिया।

यह सम्मान नहीं, बर्बादी का जश्न': संसद में धर्मद्र प्रधान के अभिनंदन पर राहुल गांधी का तंज, सरकार को घेरा

नई दिल्ली। संसद परिसर में सोमवार को जबरदस्ती राजनीतिक बवाल देखने को मिला। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मद्र प्रधान का एनडीए सांसदों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को अड़े छात्रों पर सख्त आरोप लगाए। उन्होंने इस स्वागत समारोह को देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया।



युवाओं का आक्रोश और मंत्री का इस्तीफा
राहुल गांधी ने पूर्व शिक्षा मंत्री पर सीधे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि धर्मद्र प्रधान का इस्तीफा किसी नैतिकता के आधार पर नहीं आया था। देश के छात्र और युवा लंबे समय से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। युवाओं के इसी भारी आक्रोश के डर से उन्हें पद छोड़ना पड़ा। विपक्ष के नेता ने हाल की दुखद घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लचर व्यवस्था के कारण हाल ही में

26 मासूम बच्चों की जान चली गई। लाखों योग्य छात्र आज अपने हक के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। इन तमाम स्थितियों के लिए सीधे तौर पर पूर्व शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। संसद के मकर द्वार पर राजनीतिक तमाशा! संसद के मकर द्वार पर एनडीए सांसदों ने धर्मद्र प्रधान को मफा पहनाई और नरेशजी की। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस पूरे

घटनाक्रम पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नियम व्यवस्था के कार्यालय में शिक्षा व्यवस्था तबाह हुई, उसका अभिप्रेत करना सरमाहक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई सम्मान समारोह नहीं है। यह तो देश के करोड़ों बच्चों की तबाही का जश्न मनाते जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष इस गंभीर संकट को दबाने के लिए जानबूझकर राजनीतिक तमाशा बना रहा है।

देश के छात्र और युवा लंबे समय से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। युवाओं के इसी भारी आक्रोश के डर से उन्हें पद छोड़ना पड़ा। विपक्ष के नेता ने हाल की दुखद घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लचर व्यवस्था के कारण हाल ही में 26 मासूम बच्चों की जान चली गई। लाखों योग्य छात्र आज अपने हक के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं।

पूरा देश देख चुका है कि धर्मद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में भी पेपर लीक के लिए माफी नहीं मांगी। उन्हें उन्होंने छात्रों पर तो गुमराह होने का आरोप लगा दिया। इसके बाद केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। जयराम रमेश ने भी भाजपा से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने पूछा कि पार्टी आखिर धर्मद्र प्रधान का किस बात के लिए अभिनंदन कर रही है? उन्होंने सवाल उठाया, 'क्या पेपर लीक, चरमराती शिक्षा व्यवस्था, छात्रों पर लाठीचार्ज और फेटेर वन चलाए जाने के बावजूद प्रधान का काम तारीफ के काबिल था? अगर नहीं, तो फिर यह सम्मान किसलिए दिया जा रहा है? अगर आर, तो क्या भाजपा देश के युवाओं और छात्रों को यही संदेश देना चाहती है?' कठिन ने माफ किया कि देश का युवा इस पूरे वाक्य के दो देख रहा है और सरकार से इन गंभीर सवालों के सीधे जवाब मांगत है।

एक और बड़ा आंदोलन! सीजेपी के बाद ई20 जनता पार्टी ने किया संसद मार्च का ऐलान

नई दिल्ली। एथनॉल मिले पेट्रोल यानी ई20 के खिलाफ चल रहा विरोध अब एक नए राजनीतिक और सामाजिक अभियान का रूप लेता दिखाई दे रहा है। ई20 जनता पार्टी नाम से चल रहा यह अभियान इन दिनों तेजी से चर्चा में है। पार्टी ने संसद तक मार्च करने का ऐलान किया है। इसकी तुलना कोकरोच जनता पार्टी के उस आंदोलन से भी की जा रही है, जिसने पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर संसद तक पैदल मार्च किया था। सोशल मीडिया पर ई20 जनता पार्टी के समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसके अभियान को काफी लोगों का समर्थन मिल रहा है। ई20 जनता पार्टी का कहना

है कि मौजूदा एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी में कई कमियां हैं। पार्टी का दावा है कि अगर नीति में सुधार किया जाए तो पेट्रोल की कीमत 80 से 90 रुपये प्रति लीटर तक लार्इ जा सकती है। पार्टी का यह भी कहना है कि बेहतर पॉलिसी के जरिए किसानों को भी अधिक फायदा पहुंचाया जा सकता है। उनका मानना है कि यह समय पॉलिसी की कमियों को दूर करने का है, न कि उन कमियों का बचाव करने का। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग भी कर रही है।

ई20 जनता पार्टी की मुख्य मांग
ई20 जनता पार्टी की मुख्य मांग यह है कि देशभर में ई0 पेट्रोल भी उपलब्ध करवा जाए और लोगों को अपनी पर्सद का ईंधन चुनने का



अधिकार मिले। पार्टी चाहती है कि उपभोक्ताओं को ई0, ई20 और ई85 जैसे विकल्पों में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता हो। उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी के लिए शुद्ध पेट्रोल

यानी ई0 चाहिए, तो उसे वह खरीदने की अनुमति मिलनी चाहिए। पार्टी का मानना है कि किसी एक प्रकार के ईंधन को लोगों पर जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए, साथ ही अलग-अलग प्रकार के ईंधन की कीमतों में

भी स्पष्ट अंतर होना चाहिए। **टैक्सी और परिवहन संगठनों ने मुद्दे को गंभीर बताया**
टैक्सी और परिवहन संगठनों ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सजय सपाट ने कहा है कि देशभर के टैक्सी चालक, बस संचालक, टूरिस्ट वाहन मालिक, ट्रांसपोर्ट, ऑटो चालक और ट्र ऑपरटर 4 अगस्त 2026 को पहले जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद संसद की ओर मार्च करेंगे। इसके अलावा देश के अलग-अलग राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। उनका कहना है कि ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कई वाहन मालिक परेशान हैं, उनका

दावा है कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। **गांधीवादी तरीके से मार्च करने की तैयारी**
पार्टी ने यह भी बताया है कि उसके कार्यकर्ता गांधीवादी तरीके से मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सड़कों की गई एक पोस्ट के अनुसार, तत्कालीन पुनर्वास्त की टीम भारत की अगुवाई में 31 जुलाई 2026 को इंडिया गेट से संसद तक एक मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च में ई10 और ई0 जैसे विकल्प उपलब्ध कराने, ई20 को 20 प्रतिशत सस्ता करने और शुद्ध पेट्रोल की कीमत 80 से 90 रुपये प्रति लीटर रखने जैसी मांग उठाई जाएगी।

ई20 जनता पार्टी का अभी तक कोई आधिकारिक संस्थापक या औपचारिक संगठन सामने नहीं आया है। फिलहाल इसे नागरिकों द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल अभियान माना जा रहा है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। एक्स पर इस अभियान से जुड़े अकाउंट को लगभग 48 हजार लोग फॉलो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख 77 हजार से अधिक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर किए गए अपने अलग-अलग पोस्ट में ई20 जनता पार्टी से जुड़े लोग एथनॉल मिले पेट्रोल को लोगों पर थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं।

पुलिस ने 2,873 लोगों की पहचान की, इनमें 989 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले, भूमिका की होगी जांच



नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर गत सोमवार को हुए सीजेपी के प्रदर्शन की जांच में चीफने जाले तथा समने आए हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल 2,873 लोगों की पहचान की गई है। इनमें से 989 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। पुलिस के अनुसार, इनमें दहश के 101 आरोपी, लूट व छेड़ों

के 284 आरोपी तथा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ रीम उठाई गई शामिल हैं। इसके अलावा झपटमारी के 135, आर्म्स एक्ट के 229, एनडीपीएस एक्ट के 67 और अफ़्फ़र के 19 आरोपी भी लिस्ट किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 20 से अधिक एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें करीब 15

एफआईआर पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की शिकार पर दर्ज हुई हैं, जबकि शेष शिकायतें महिला एक्कारों और अन्य निजी पीड़ितों की ओर से दर्ज कइ गई हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मोमोटीवी फूटन के आधार पर हिंसा, पुलिसकर्मियों पर हमले और सरकारी व निजी वाहनों में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की गई। जांच में यह भी सामने आया कि कई आरोपी आदतन अपराधी हैं। हत्या के 101 आरोपियों में से 42 पर ये या अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 12 के खिलाफ 10 या उससे अधिक मामले हैं। इसी वजह लूट और छेड़ों के 284 आरोपियों में से 155 पर नई मुकदमे दर्ज हैं और 31 के खिलाफ 10 से अधिक मामले लंबित हैं। दिल्ली पुलिस ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

बिहार सरकार का बड़ा फैसला: नीट पेपर लीक प्रदर्शन में छात्रों पर दर्ज सभी केस होंगे वापस

नेशनल डेस्क। नीट पेपर लीक के विरोध में बिहार में हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। सरकार ने छत्र आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी पुलिस मामलों को वापस लेने का फैसला किया है।



26 जुलाई से पहले के सभी मामले होंगे खत्म
बिहार सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव द्वारा पेश गई जानकारी के अनुसार, 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसके साथ ही, तोड़फोड़ और हिंसा के आरोपों में शामिलों में लिए गए या गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है। तेज प्रताप यादव की होगी रिहाई

इस फैसले का सबसे बड़ा असर राजनीतिक गतिरोध में भी देखने को मिलेगा। विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजे गए राजन नेत्र प्रताप यादव की रिहाई का खसत अब साफ हो गया है। सरकार के फैसले के बाद पुलिस अब संबंधित अदालत को केस वापसी की जानकारी देगी, जिसके आधार पर उन्हें जेल से बाहर लाया जाएगा। दबाव और छात्र संगठनों का दबाव गौरतलब है कि नीट पाठशाला की

लेकर हुए प्रदर्शनों में छात्रों पर हुई कार्रवाई का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर थे। इसके अलावा, 'कोकरोच जनता पार्टी' ने भी बिहार और चंपारण में पुलिस एक्शन पर आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी थी कि यदि केस वापस नहीं हुए तो वे देनाबा जंतर-मंतर पर घटना देंगे। छात्रों को मिली बड़ी राहत नीट पेपर लीक के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान कई छात्रों पर गंभीर धाराओं में मामलों दर्ज किए गए थे, जिससे उनके भविष्य पर लंबाचल लटकी हुई थी। सरकार के इस कदम से न केवल छात्रों को राहत मिली है, बल्कि राज्य में जारी राजनीतिक गतिरोध के भी कम होने की उम्मीद है।

धर्मद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा!

लखनऊ। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षामंत्री का इस्तीफा होने के बाद कोकरोच जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश

में मोर्चा खोल दिया है। यूपी सरकार ने रामपुर को नीट यूनिवर्सिटी को गिराने का आदेश दिया है।

सक्षम भारत की बेवसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।